माननिए न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के समक्ष

टी.एस. भट्टी - याचिकाकर्ता बनाम
हरियाणा राज्य- उत्तरदाताओं।

2008 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7667

मई 12, 2017

भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 - याचिकाकर्ता, जो डीएफएससी के रूप में काम कर रहा था, को सितंबर, 1989 में गेहूं की बोरियों के क्षतिग्रस्त/कमी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक ज्ञापन दिया गया था - याचिकाकर्ता ने अक्टूबर, 1989 में जवाब दायर किया - 6 साल तक कुछ नहीं हुआ, फिर अक्टूबर, 1995 में, याचिकाकर्ता ने हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियमों के नियम 7 के तहत उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना दी, (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दो आरोप-पत्रों के आधार पर - निरीक्षण रिपोर्ट न भेजने और पर्यवेक्षी नियंत्रण की कमी के आरोप - आरोप पत्रों के संबंध में याचिकाकर्ता का उत्तर असंतोषजनक पाया गया, जांच अधिकारी नियुक्त किया गया - जांच अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि आरोप सिद्ध नहीं हुए - सक्षम प्राधिकारी ने असहमति नोट दर्ज किया और वसूली तथा उपदान रोकने के आदेश पारित किए - यह देखते हुए कि विभाग को हुई हानि के लिए कोई अन्य अधिकारी जिम्मेदार था, और याचिकाकर्ता की ओर से पर्यवेक्षी नियंत्रण की कोई कमी नहीं थी, उच्च न्यायालय ने याचिका की अनुमति दी और वसूली के आदेशों को रद्द कर दिया और ब्याज के साथ ग्रेच्युटी और पेंशन के भुगतान का आदेश दिया - रिट याचिका की अनुमति दी गई.

अभिनिर्धारित किया की मेरा विचार है कि एक बार जब जांच अधिकारी द्वारा यह माना जाता है कि पर्यवेक्षण की कोई कमी नहीं है, इसलिए, केवल कुछ नियमों के आधार पर कि पर्यवेक्षी अधिकारी भी जिम्मेदार है, याचिकाकर्ता को सीधे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि याचिकाकर्ता की ओर से पर्यवेक्षण

की कमी थी। आरोप पत्र जारी करने के लिए याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण मिलने के बाद विभाग लगभग छह साल तक चुप रहा। जांच वर्ष 2002 में पूरी हुई और असहमति नोट पांच साल बाद वर्ष 2007 में दर्ज किए गए और सजा के आदेश वर्ष 2008 में पारित किए गए। यदि कमी और हानि होती है, तो कोई कारण नहीं है कि आरोप-पत्र जारी करने से पहले मामले को छह साल तक लंबित रखा जाए।

(पैरा 19)

यह भी अभिनिर्धारित किया की , इसके अलावा, जांच रिपोर्टों में, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता की ओर से पर्यवेक्षण की कोई कमी नहीं है। गलती तत्कालीन निरीक्षक श्री बीडी गोयल द्वारा की गई थी,पीआर सेंटर, टोहाना और याचिकाकर्ता की कार्रवाई वैध थी। यह लेखा शाखा का कर्तव्य था कि वह बिलों की जांच करे और सत्यापन के बाद, याचिकाकर्ता के समक्ष इसे रखे, जिसने इस पर हस्ताक्षर किए। पीआर सेंटर, टोहाना के बीडी गोयल और अन्य कर्मचारियों द्वारा विभाग को नुकसान पहुंचाया गया है। याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है कि वह जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक, हिसार के रूप में तैनात था और पीआर सेंटर टोहन उक्त जिले में आता है.

(पैरा 20)

एस.के. सूद, एडवोकेट के साथ व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

अपूर्व गर्ग, उप महाधिवक्ता, हरियाणा।

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह

1. याचिकाकर्ता, जो सेवानिवृत्त जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक, हिसार है, ने दिनांक 17.10.1995 (अनुलग्नक पी-3), आरोप पत्र दिनांक 11.12.1996 (अनुलग्नक पी-4), कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.03.2007 और 09.03.2007 (अनुबंध पी-11 और पी-12) और वसूली आदेश दिनांक 07.02.2008 और 05/29.03.2008 (अनुबंध पी-15 और पी-16) को रद्द करने के लिए उप्रेषण की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए भारत के

संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है। परमादेश की प्रकृति में एक रिट भी उत्तरदाताओं को ग्रेच्युटी जारी करने और ब्याज @ 12% प्रति वर्ष के साथ पेंशन जारी करने का निर्देश देने के लिए मांगी गई है।

2. याचिकाकर्ता, जो पूर्व में हिसार में जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक के रूप में कार्यरत था और बाद में भिवानी में तैनात था, को 19/21.09.1989 (अनुलग्नक पी -1) का एक ज्ञापन मिला, जिसमें गेहूं की बोरियों को नुकसान और कमी से संबंधित नुकसान और पीआर सेंटर टोहाना के सत्यापन के बारे में चिंताओं को संबोधित किया गया था। यह केंद्र हिसार में जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान याचिकाकर्ता के नियंत्रण में था। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता पीआर सेंटर टोहाना का निरीक्षण करने में विफल रहा और निरीक्षण रिपोर्ट जमा नहीं की। याचिकाकर्ता ने अपना रुख स्पष्ट करने के लिए 25.10.1989 (अनुबंध पी-2) को ज्ञापन का जवाब दिया। हालांकि, अगले छह वर्षों के लिए कोई और विकास नहीं हुआ। 17.10.1995 को, याचिकाकर्ता को संलग्न आरोप-पत्र (अनुलग्नक पी -3) के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम 1987 के नियम 7 के तहत आसन्न कार्रवाई के बारे में अधिसूचित किया गया था। दिनांक 11.12.1996 का एक और आरोप-पत्र (अनुबंध पी-4) आया। याचिकाकर्ता ने इन आरोप-पत्रों के जवाब दिए, लेकिन उन्हें असंतोषजनक माना गया। इसके बाद, श्री नरेश गुलाटी, आईएएस, उद्योग आयुक्त । को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। नियमित विभागीय जांच के बाद, जांच अधिकारी ने दिनांक 07.11.2002 और 06.12.20012 (अनुबंध पी-7 और पी-8, क्रमशः) दोनों आरोप-पत्रों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की।

3. प्रारंभिक आरोप-पत्र से संबंधित दिनांक 07.11.2002 की जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-7) में कहा गया है कि रिकॉर्ड में साक्ष्य और

सामग्री में अंतर के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप अप्रमाणित रहे। इसी प्रकार, दूसरे आरोप-पत्र के संबंध में दिनांक 06.12.2002 की जांच रिपोर्ट (अनुबंध पी-8) में दर्शाया गया है कि साक्ष्य के अभाव में कर्मचारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके।

4. सक्षम प्राधिकारी ने 2007 में जांच रिपोर्ट से सहमति नहीं दी और अलग-अलग नोट दर्ज करके असहमति व्यक्त की। उसी वर्ष, सक्षम प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट से असहमति जताई और याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के जवाब के बाद, दंडात्मक आदेश दिनांक 07.02.2008 (अनुबंध पी-15) और 29.03.2008 (अनुबंध पी-16) जारी किए गए, जिनमें क्रमशः 1,69,739.32/- रुपये और 2,27,537.35 रुपये का जुर्माना लगाया गया। याचिकाकर्ता विभिन्न आधारों पर इन आदेशों को रद्द करने की मांग कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि उनकी कोई गलती नहीं थी और जांच अधिकारी द्वारा बरी किए जाने के बावजूद, उन्हें गलत तरीके से दोषी माना गया है।

5. लिखित बयान में, प्रतिवादी नंबर 1 ने तर्क दिया कि खाद्य और आपूर्ति विभाग, हरियाणा, केंद्रीय एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम को स्टॉक भेजने तक केंद्रीय पूल के लिए गेहूं/धान खरीद एजेंसियों में से एक के रूप में कार्य करता है। विभाग चोरी या लापरवाही के कारण नुकसान या क्षति के खिलाफ स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। वित्तीय वर्ष 1989-90 में, गेहूं खरीद के एकमात्र पर्यवेक्षक के रूप में, याचिकाकर्ता ने मेसर्स सुभाष चंद प्रेमचंद, टोहाना से कुल 3751 गेहूं के बैग खरीदे। इनमें से 1240 बैग बिलिंग-कम-पेमेंट एजेंट के माध्यम से अधिग्रहित किए गए थे, और 2511 बैग सीधे उसी फर्म से खरीदे गए थे। विशेष रूप से, 2440 बैग वितरित नहीं किए गए थे, और याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत से पीआर सेंटर, टोहाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री बीडी गोयल द्वारा रजिस्टर पीआर -6, पीआर -9 और

पीआर -86 में धोखाधड़ी की गई थीं। सभी बैगों के लिए भुगतान उनकी रसीद की पुष्टि किए बिना पार्टी को किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी विभाग के लिए ब्याज के साथ 5,27,535.30 / याचिकाकर्ता ने सर्कल कार्यालय में वित्तीय संरक्षक/सलाहकार अनुभाग अधिकारी से सत्यापन के बिना भुगतान के लिए विशेष रूप से संख्या 1141/22 दिनांक 03.05.1989 और 1141/23 दिनांक 12.05.1989 को गलती से खरीद बिलों पर हस्ताक्षर किए।

6. यह भी दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 07.11.2002 (अनुलग्नक पी -7) की रिपोर्ट में आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि रिकॉर्ड पर साक्ष्य/सामग्री में लिंक गायब थे। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति जताई और निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता पर 1,69,739.32/- रुपये का जुर्माना लगाते हुए आरोपों की पुष्टि की गई थी।

7. दूसरे मामले में, स्टॉक में हेराफेरी के संबंध में शिकायतें सीएम फ्लाइंग स्क्वायड को 1989 में प्राप्त हुई थीं। दिनांक 28-03-1989 को दस्ते ने पीआर सेंटर, टोहाना में गोदामों का निरीक्षण किया लेकिन अभिलेखों और गोदामों के निरीक्षण को रोकते हुए निरीक्षणालय स्टाफ अनुपस्थित पाया। राज्य सरकार के निर्देश के बाद, खाद्य और आपूर्ति विभाग, हरियाणा ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, हिसार को पीआर सेंटर, टोहाना का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। श्री बीएम वोहरा, तत्कालीन डीएफएसओ, हिसार के नेतृत्व में एक टीम ने 12.07.1989 से 26.07.1989 तक एक विशेष भौतिक सत्यापन किया, जिसमें निरीक्षणालय कर्मचारियों द्वारा कई खामियों का पता चला। 01.09.1989 को उप निदेशक (पी) और उप नियंत्रक खाद्य लेखा की अध्यक्षता में एक अन्य टीम को भौतिक सत्यापन करने के लिए भेजा गया था, जिसमें केंद्र के कर्मचारियों और पर्यवेक्षी प्रभारी डीएफएससी और

डीएफएसओ, हिसार द्वारा लापरवाही के कारण कुल 45,92,142.52 रुपये के नुकसान का खुलासा किया गया था। नतीजतन, निरीक्षणालय कर्मचारियों को 23.09.1989 को निलंबित कर दिया गया था, और विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र के तत्कालीन प्रभारी एसएचबीडी गोयल, आईएफएस को दिनांक 10/11.03.2003 के आदेश के माध्यम से बर्खास्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता, गेहूं स्टॉक/स्टॉक लेखों के लिए जिले के एकमात्र प्रभारी के रूप में, 7254 पुराने स्टॉक बैग में विसंगति के लिए जिम्मेदार था, जो मानक वजन से हल्का था। कर्मचारी पीआर 9, 6, 39 आदि जैसे आवश्यक रजिस्टर प्रदान करने में भी विफल रहे।

8. भौतिक सत्यापन प्रक्रिया और श्री सुशील कुमार, आईएफएस को जिम्मेदारियों के संक्रमण दोनों के दौरान, यह पता चला कि श्री बीडी गोयल, आईएफएस ने वर्ष 1988-90 के लिए गेहूं के स्टॉक और स्टॉक लेखों में नुकसान और कमी पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिम्मेदारी पूरी तरह से निरीक्षणालय कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया था, और याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी पर्यवेक्षी चूक की अवहेलना की गई थी। पत्र में दिनांक 09.12.1985 (अनुबंध आर-1) के निर्देशों का हवाला दिया गया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जिला खाद्य और आपूर्ति अधिकारी/जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक जैसे पर्यवेक्षी अधिकारी स्टॉक की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपने कर्मचारियों पर ढीला नियंत्रण लापरवाही का कारण बन सकता है। पत्र में जोर देकर कहा गया है कि पर्यवेक्षी अधिकारियों को नियमित रूप से अपने दायरे में आने वाले स्टॉक और स्टॉक लेखों का निरीक्षण करना चाहिए, मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। इसके अलावा, इसने पर्यवेक्षी अधिकारियों को अन्य निरीक्षणालय कर्मचारियों के साथ-साथ उनके संबंधित सर्कल में स्टॉक और स्टॉक लेखों के नुकसान के लिए

सीधे जवाबदेह ठहराने के राज्य सरकार के निर्णय को रेखांकित किया। पत्र में पीआर मैनुअल पार्ट-I, पैराग्राफ 1.15 और 1.18 के संदर्भों का भी हवाला दिया गया है, जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

पैरा 1.15

"जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) को यह सुनिश्चित करने के तरीकों को नियोजित करना चाहिए कि वह खरीदे गए सभी अनाज और अन्य स्टॉक लेखों की सटीक जवाबदेही के साथ-साथ आवंटित धन के उचित उपयोग से संतुष्ट है, ताकि सरकार को किसी भी परिहार्य नुकसान को रोका जा सके। डीएफएससी स्टॉक की उचित प्राप्ति, भंडारण और जारी करने की देखरेख की जिम्मेदारी रखता है।

पैरा 1.18

"डीएफएससी से उम्मीद की जाती है कि जब सरकारी धन से किए गए खर्चों के प्रबंधन की बात आती है तो वह एक विवेकपूर्ण व्यक्ति की तुलना में सतर्कता का स्तर रखेगा। इसमें सरकारी स्टॉक से अनाज और अन्य स्टॉक लेखों की प्राप्ति, भंडारण, जारी करने और बिक्री की देखरेख करना शामिल है, जिसमें देखभाल का स्तर समान है जो अपने स्वयं के धन के प्रबंधन और संबंधित सामानों को संभालने में प्रयोग करेगा."

9. सक्षम प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि 2,27,537.35/- रुपये की वसूली से संबंधित प्रस्तावित जुर्माना 45,50,747.22/- रुपये की कुल हानि का 5% है। नतीजतन, वसूली की निर्दिष्ट सजा याचिकाकर्ता पर लगाई गई थी। यह दावा किया गया था कि श्री बीडी गोयल, आईएफएस, पीआर सेंटर, टोहाना के तत्कालीन प्रभारी, को राजनीतिक प्रभाव में नहीं रखा गया था।

10. मैंने दोनों पक्षों के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना है और केस फाइल की पूरी तरह से जांच की है।

11. चार्जशीट और जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने पर, यह स्पष्ट है कि पहली जांच के संबंध में, आरोप लगाए गए थे कि याचिकाकर्ता ने पीआर सेंटर, टोहाना में गोदाम में स्टॉक को भौतिक रूप से सत्यापित किए बिना 2440 बैग गेहूं के भुगतान को मंजूरी दे दी थी।

12. असहमति नोट पीआर मैनुअल के पैरा 1.15, भाग I, II और III को संदर्भित करता है ताकि याचिकाकर्ता को नुकसान के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके।

13. इसी तरह, दूसरी जांच में, याचिकाकर्ता को दोषी खोजने और जांच रिपोर्ट से असहमति जताने के लिए उसी नियम को लागू किया गया था।

14. तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने पर, यह देखा गया है कि शुरू में, याचिकाकर्ता को सितंबर 1989 में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने एक महीने के भीतर नोटिस का जवाब दिया। इसके बाद, प्रतिवादी विभाग छह साल तक निष्क्रिय रहा। अचानक, 1995 में, 17.10.1995 को, एक आरोप-पत्र तामील किया गया, उसके बाद 11.12.1996 को एक और आरोप-पत्र दिया गया। दोनों आरोप-पत्रों ने याचिकाकर्ता पर पीआर सेंटर, टोहाना में अपर्याप्त पर्यवेक्षण का आरोप लगाया, जहां श्री बीडी गोयल पर्यवेक्षी अधिकारी थे, और लिखित बयान के अनुसार, उन पर आरोप लगाया गया और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

15. सवाल उठता है कि क्या याचिकाकर्ता को पर्यवेक्षी चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

16. इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि स्टॉक की कमी के बारे में जानने के बाद, याचिकाकर्ता ने श्री बीडी गोयल के खिलाफ

प्राथमिकी दर्ज की, जिसे बाद में अदालत ने बरी कर दिया था। प्रथम आरोप पत्र की दिनांक 07.11.2002 (अनुलग्नक पी-15) की जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि आईएएस अधिकारी द्वारा की गई जांच में पाया गया कि लेखा शाखा ने खरीद बिल को डीएफएससी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले उसकी गहन छानबीन और सत्यापन किया। याचिकाकर्ता के पास लेखांकन मामलों में विशेषज्ञता की कमी थी और अधीनस्थ कर्मचारियों पर निर्भर था। जांच अधिकारी ने आगे कहा कि गेहूं खरीदना और बेचना इंस्पेक्टर का कर्तव्य था, और लेखा शाखा संबंधित निरीक्षक से प्राप्त होने के बाद संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के लिए बाध्य थी। जांच अधिकारी को ऐसा कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं मिला जो याचिकाकर्ता की ओर से किसी गुप्त मकसद का संकेत देता हो। विभाग ऐसा कोई सबूत पेश करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता ने कोई व्यक्तिगत लाभ प्राप्त किया है। जांच अधिकारी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि लेखा शाखा के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को गुमराह किया और खरीद बिल संख्या 1141/22, दिनांक 03.05.1989 के लिए भुगतान जारी करने की सुविधा प्रदान की।

17. दूसरे आरोप-पत्र से संबंधित दिनांक 06.12.2002 की दूसरी जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक पी-8) में, जांच अधिकारी ने रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों की समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि याचिकाकर्ता के कार्यकाल के दौरान भौतिक सत्यापन के अनुसार कमी देखी गई थी, लेकिन इसे निश्चित रूप से उसकी अवधि या पहले की समय सीमा के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। विभाग द्वारा आपूर्ति किए गए रिकॉर्ड की जांच में याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी लापरवाही का पता नहीं चला, जिसने कमी के बारे में जानने पर त्वरित कार्रवाई की। जांच अधिकारी ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता ने प्रधान कार्यालय के निर्देशों का पालन करके, एक टीम का गठन करके, पूरी तरह से रिकॉर्ड पूरा करने का निर्देश दिया, और श्री बीडी गोयल, इंस्पेक्टर, पीआर सेंटर,

टोहाना की उपस्थिति में पीआर सेंटर, टोहाना में संग्रहीत लेखों का सत्यापन करके एक वास्तविक इरादे का प्रदर्शन किया।

18. पीआर सेंटर, टोहाना में डीएफएसओ श्री बीडी गोयल की उपस्थिति में नामित टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। यह दस्तावेज किया गया था कि, निदेशक के निर्देश पर, याचिकाकर्ता ने तुरंत 16.08.1989 को एफआईआर नंबर 233 दर्ज की। मामले के एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के बाद, जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने अपने पर्यवेक्षी कर्तव्यों को पूरा करने में उचित देखभाल और सावधानी की कमी नहीं दिखाई है। जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के ईमानदार प्रयासों और वास्तविक इरादों को स्वीकार किया। कमी के उभरने के छह से सात साल बाद आरोपित याचिकाकर्ता को सबूतों की कमी के कारण दोषी नहीं माना गया।

19. मेरी राय में, एक बार जब जांच अधिकारी यह स्थापित कर देता है कि पर्यवेक्षण की कोई कमी नहीं है, तो याचिकाकर्ता को केवल पर्यवेक्षी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने वाले नियमों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता है जब तक कि याचिकाकर्ता द्वारा पर्यवेक्षण में कमी साबित न हो। चार्जशीट जारी करने से पहले याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण मिलने के लगभग छह साल बाद विभाग की लंबी चुप्पी सवाल खड़े करती है। जांच 2002 में समाप्त हुई, 2007 में असहमति नोट दर्ज किए गए और 2008 में सजा के आदेश जारी किए गए। कमी और नुकसान के अस्तित्व के बावजूद, मामले को संबोधित करने में विस्तारित देरी अनुचित लगती है।

20. इसके अलावा, जांच रिपोर्टों ने संकेत दिया कि याचिकाकर्ता की ओर से पर्यवेक्षण की कोई कमी नहीं थी। इस गलत काम के लिए श्री बीडी गोयल, तत्कालीन इंस्पेक्टर, पीआर सेंटर, टोहाना को जिम्मेदार ठहराया गया था और याचिकाकर्ता के नेक इरादे को मान्यता दी गई थी। यह लेखा शाखा का कर्तव्य था कि वह बिलों की जांच करे और सत्यापन के बाद, उन्हें याचिकाकर्ता को हस्ताक्षर

के लिए प्रस्तुत करे। बीडी गोयल और अन्य पीआर सेंटर, टोहाना कर्मचारियों के कार्यों के कारण विभाग को नुकसान हुआ। याचिकाकर्ता को केवल हिसार में जिला खाद्य और आपूर्ति नियंत्रक के रूप में अपनी पोस्टिंग के आधार पर उत्तरदायी ठहराना, जहां पीआर सेंटर टोहाना स्थित था, उचित नहीं है।

21. जांच अधिकारी के स्पष्ट निष्कर्षों को देखते हुए, मेरी राय है कि मौजूदा परिस्थितियों में लगाए गए दंड आदेश उचित नहीं हैं। विभाग ने बिना किसी पर्याप्त कारण के याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए जवाबदेह ठहराया, जो वास्तव में श्री बीडी गोयल, तत्कालीन निरीक्षक-सह-प्रभारी, पीआर सेंटर, टोहाना के कारण हुआ था।

22. याचिकाकर्ता 30.09.1990 को सेवा से सेवानिवृत्त हुआ, और इसलिए, चल रही पूछताछ के दौरान सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पांच साल तक विभाग चुप रहा।

23. नतीजतन, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने के लिए कोई कानूनी या न्यायसंगत आधार नहीं प्रतीत होता है। जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को निर्दोष पाया, और एक ज्ञापन के आधार पर असहमति नोट पर्यवेक्षी कर्तव्यों में कथित कमियों के लिए याचिकाकर्ता के अपराध को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसे देखते हुए, दिनांक 17.10.1995 (अनुबंध पी-3), दिनांक 11.12.1996 का आरोप-पत्र (अनुबंध पी-4), दिनांक 09.03.2007 और 09.03.2007 के कारण बताओ नोटिस (अनुबंध पी-11 और पी-12), और दिनांक 07.02.2008 और 05/29.03.2008 (अनुबंध पी-15 और पी-16) के वसूली आदेश एतद्द्वारा रद्द किए जाते हैं। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन और याचिकाकर्ता से वसूल की गई राशि को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ जारी करें।

24. ऐसे में वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाता है।

पी एस बाजवा

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सचिन सिंघल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार , हरियाणा